अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

मैं, आपकी कंपनी की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, जिसमें सफल उपलब्धियों से परिपूर्ण एक और वर्ष का निरूपण किया गया है। महामारी की दूसरी लहर के कारण वित्तीय वर्ष 2021–22 की शुरुआत हमारे साथ–साथ सभी के लिए कठिनाईयों से भरी थी। विद्युत क्षेत्र के लिए समर्पित एक वित्तीय संस्थान के रूप में, हम उद्योग के सामने आने वाले प्रचालन मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं और अर्थव्यवस्था के समग्र सुधार की आशा करते हैं। अनुकूलन क्षमता और लचीलेपन के साथ, अनिश्चितताओं से भरी इस अवधि के दौरान भी हमने अपने हितधारकों के हितों की रक्षा की है और प्रभावपूर्ण प्रदर्शन किया है।

आपकी कंपनी ने अपने लागत प्रभावी संसाधन प्रबंधन और सुदृढ़ वित्तीय नीतियों के फलस्वरूप, अब तक का सबसे अधिक लाभ अर्थात् ₹10,046 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष से 20% अधिक था। 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी का निवल मूल्य

₹50,986 करोड़ था, जो एक साल पूर्व के निवल मूल्य से 17% अधिक था, जो कंपनी द्वारा किए गए उल्लेखनीय मूल्यवर्धन को इंगित करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में, आरईसी की सकल ऋण परिसंपत्ति बही 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार ₹3,85,371 करोड़ के अब तक के सबसे उच्च स्तर पर थी। आपकी कंपनी ने अपने घरेलू ऋण लिखतों के लिए "एएए" रेटिंग और "बीएए3" और "बीबीबी–" की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग बनाए रखी, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग के बराबर है। इन सुदृढ़ मूलभूत सिद्धांतों को भावी–तत्परता दृष्टिकोण के साथ संयोजित किया गया है, जो हमें आने वाले समय के लिए सशक्त बनाता है।

अपने कारोबारिक लक्ष्यों के अतिरिक्त, आरईसी विद्युत क्षेत्र के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार का एक विश्वसनीय भागीदार भी रही है और बनी रहेगी। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि देश के दूर–दराज के कोने–कोने में बिजली पहुंच गई है। दीनदयाल *उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)* और *प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)* जैसी प्रमुख स्कीमें, जिनके लिए आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय की नोडल एजेंसी थी, को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और वास्तव में एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भारत – *उज्जवल भारत* की नींव रखी। बिजली क्षेत्र अब आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन, उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमतों में कमी और दक्षता और सेवा प्रदायगी के इष्टतमीकरण के लिए तैयार है। हमें सरकार की ₹3 लाख करोड़ की सुधार–आधारित और परिणाम–संबद्ध संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (*आरडीएसएस)* में अपनी भागीदारी पर गर्व है, जो इस दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2022 की शुरूआत में, महामारी के कारण पूरे विश्व में मुद्रास्फीति, खाद्य कीमतों में वृद्धि और बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं के परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले की अपेक्षा कमजोर स्थिति में थी। भू–राजनीतिक संघर्ष और यूक्रेन में युद्ध के कारण अनिश्चितताएं और बढ़ गईं। हालांकि, पूरे विश्व में सामान्य कारोबार की धारणा में सुधार हो रहा है। यहां तक कि आपूर्ति श्रृंखलाओं में महामारी के बाद अपरिहार्य दबाव का सामना करने के बावजूद भी, माल और सेवाओं के कारोबार में तेजी से वृद्धि हुई और यह लगातार मजबूत होता जा रहा है। कारोबार और विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक कारोबार का मूल्य वर्ष 2021 में 28.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो कि महामारी के प्रकोप से ठीक पहले अर्थात् वर्ष 2020 की तुलना में 25% और वर्ष 2019 की तुलना में 13% की वृद्धि है। सेवाओं में कारोबार भी काफी हद तक बढ़कर, लगभग इसके महामारी–पूर्व स्तर तक पहुंच गया।

हालांकि, पिछले पूर्वानुमानों की तुलना में मुद्रास्फीति लंबी अवधि के लिए उच्च स्तर पर बने रहने की उम्मीद है। वर्ष 2022 के लिए, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 5.7% तथा उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 8.7% होने का अनुमान है। जिन देशों की आर्थिक नीतियां कमजोर हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अधिक निर्भर है, उनके इस परिदृश्य में अधिक प्रभावित होने की संभावना है। यहीं पर हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए मंत्र *आत्मनिर्भर भारत* के महत्त्व का एहसास होना चाहिए।

भारत का विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में प्रभुत्व जारी है। आरबीआई का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2% होगी, जबकि एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2022–23 में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.5% और वर्ष 2023–24 में 8% रहेगी। हमने एक बेहद सफल राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम का अनुभव किया, जो हमारे देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए महामारी से होने वाले नुकसान को रोकने में सहायक रहा। राजकोषीय, मौद्रिक और स्वास्थ्य पैकेजों सहित सरकार की व्यापक कोविड प्रतिक्रियाओं के कारण समय रहते विषम परिस्थितियों का शमन किया गया। विद्युत मांग, श्रम भागीदारी और रेलवे माल यातायात जैसे सामाजिक–आर्थिक संकेतकों में सुधार के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद, मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि यह समय अभी भी उद्योग के साथ–साथ आम नागरिकों द्वारा असावधानी बरतने का समय नहीं है। हमें एक राष्ट्र के रूप में स्वयं को मजबूत करना होगा और एक दूसरे का समर्थन करना होगा, ताकि कोई भी बाह्य कारक प्रतिकूल प्रभाव न डाल पाए।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

वर्ष 2021 में वैश्विक विद्युत मांग में 6% की वृद्धि हुई, जो आर्थिक सुधार का एक मजबूत संकेत है। भारत में संस्थापित कुल उत्पादन क्षमता 400 गीगावाट के लक्ष्य को पार कर गई है। पारेषण लाइनों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार वितरण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत–से सुधार कर रही है। डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य की सफलता के बाद सरकार की हाल ही में शुरू की गई आरडीएसएस योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थायी और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है।

आरडीएसएस के उद्देश्यों में वर्ष 2024–25 तक अखिल भारतीय स्तर पर एटी एंड सी हानियों को 12–15% तक कम करना और वर्ष 2024–25 तक एसीएस–एआरआर अंतर को शून्य करना शामिल हैं, ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि–चरण हैं। इस स्कीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर भी विशेष जोर दिया गया है।

विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में, आपकी कंपनी ने 'डिस्कॉम उपभोक्ता सेवा रेटिंग' के लिए एक ढांचा विकसित किया है, जिसमें यथेष्ट प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और कमजोर क्षेत्रों में प्रदर्शन में सुधार करने के उद्देश्य से डिस्कॉम को प्रचालन मानकों के आधार पर रेट किया गया है। आपकी कंपनी प्रमुख विनियामक प्राचलों पर आवधिक रिपोर्ट भी प्रकाशित कर रही है, जो संकलन, बेंचमार्किंग और विभिन्न यूटिलिटियों के तुलनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को एक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करती है और जहां कहीं भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपायों को उजागर करती है।

राज्य विद्युत यूटिलिटियों की बढ़ते विद्युत खरीद बकाया को संबोधित करने की दिशा में एक कदम के रूप में, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत आपूर्तिकर्ताओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने और वित्तीय अनुशासन लाने के उद्देश्य से विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 या एलपीएस नियम जारी किए हैं। आरईसी एलपीएस नियमों के तहत डिस्कॉम को उनके बकाया के समय पर भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो भारतीय विद्युत क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में मदद करेगा।

वित्तीय और प्रचालन प्रदर्शन

महामारी के बाद, श्रम मुद्दों आदि के कारण विद्युत परियोजनाओं के प्रारम्भिक उत्थान और कमीशनिंग में कुछ देरी देखी गई। एक स्पिलओवर के रूप में, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी द्वारा संस्वीकृत किए गए ऋण 54,422 करोड़ रुपये की कम सीमा में थे। ये ऋण विभिन्न पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, टी एंड डी परियोजनाओं, अल्पकालिक, मध्यम अवधि और अन्य ऋणों से संबंधित थे। वर्ष के दौरान संस्वीकृत कुल ऋणों में से 27% ऋण नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत किए गए थे। आपकी कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, निरंतर अपने हरित पोर्टफोलियो को बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, टीएंडडी परियोजनाओं और अन्य ऋणों के लिए डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के तहत प्रतिरूप वित्तपोषण सहित ₹64,150 करोड़ का संवितरण किया गया। संवितरण में *आत्मनिर्भर भारत* के तहत सरकार की चलनिधि निवेश स्कीम के तहत विभिन्न विद्युत यूटिलिटीज को ₹19,752 करोड़ का संवितरण शामिल था। उपरोक्त के अलावा, आपकी कंपनी ने विभिन्न सरकारी स्कीमों के तहत ₹5,318 करोड़ की सब्सिडी का संवितरण भी किया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आपकी कंपनी की प्रचालन आय, एकल आधार पर, ₹39,132 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल व्यापक आय ₹9,987 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ₹10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर के लिए ₹50.87 प्रति इक्विटी शेयर का उच्चतम ईपीएस दर्ज किया गया।

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 23.61% था, जो भविष्य के विकास का समर्थन करने के लिए एक सुदृढ़ क्षमता की ओर इंगित करता है। आरईसी अपने एनपीए को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है तथा दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के आईबीसी मार्ग सहित उचित माध्यमों के जरिए समाधान के लिए एक समर्पित टीम मौजूद है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंत में, आरईसी की सकल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां (चरण–III) और निवल ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तिया (चरण–III) क्रमशः सकल ऋण परिसंपत्ति का 4.45% और 1.45% थीं।

पूंजी संरचना और अधिलाभांश निर्गम

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹5,000 करोड़ थी, जिसमें ₹10/– प्रत्येक के 500 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे। निर्गत और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹1,974.92 करोड़ थी, जिसमें ₹10 प्रत्येक के 197,49,18,000 इक्विटी शेयर शामिल थे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो भारत सरकार का उपक्रम है, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 52.63% का धारक है; और शेष 47.37% इक्विटी शेयर पूंजी जनता द्वारा धारित है।

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने अपने 'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' के क्रेडिट में मौजूद ₹658.306 करोड़ की राशि का पूंजीकरण करके, 9 अगस्त, 2022 को डाक मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से 1:3, अर्थात् ₹10/– प्रत्येक के 3 मौजूदा पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के लिए ₹10/– प्रत्येक का 1 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर के अनुपात में बोनस शेयर के निर्गमन के लिए अपने शेयरधारकों अनुमोदन प्राप्त किया है। उक्त बोनस शेयरों के आबंटन के बाद, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी बढ़कर ₹2,633.22 करोड़ हो जाएगी, जिसमें ₹10 प्रत्येक के 2,63,32,24,000 इक्विटी शेयर शामिल होंगे।

लाभांश

आपकी कंपनी अपने समकक्षों में से सबसे अधिक लाभांश देने वाली कंपनियों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, कंपनी पहले ही तीन चरणों में ₹10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर के लिए ₹10.50/– प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, ₹10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर के लिए ₹4.80/– प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश 53वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यदि अनुमोदित कर दिया जाता है, तो वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल लाभांश ₹10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर के लिए 15.30/– प्रति इक्विटी शेयर के बराबर होगा, जो कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 153% है।

निगमित सुशासन

आरईसी कॉरपोरेट सुशासन में सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने और उनका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 के तहत सभी लागू अपेक्षाओं और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिव–विषयक मानकों का पालन करती है।

आपकी कंपनी में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की कमी है। हालांकि, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के पास है। हमने विद्युत मंत्रालय से स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में तेजी लाने का अनुरोध किया है और मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

नीतिगत पहल

कारोबारिक मूल्य बढ़ाने और सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी के नीतिगत ढांचे की लगातार समीक्षा, अद्यतनीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बाजार में प्रतिस्पर्धी दर्जे को बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी ने विभिन्न कारोबार–उन्मुख नीतियों की शुरुआत की और साथ ही साथ इनकी समीक्षा की, जिनमें राज्य क्षेत्र की यूटिलिटीज को सावधि ऋण के लिए नीतियां, पीएम–कुसुम स्कीम के तहत परियोजनाओं का वित्तपोषण, निजी क्षेत्र में पारेषण परियोजनाओं का मूल्यांकन और वित्तपोषण, पूर्व–भुगतान नीति, साख–पत्र नीति और राज्य क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए जोखिम मानदंड आदि शामिल हैं।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी की एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें ऋण जोखिम, प्रचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाजार जोखिम शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार के जोखिम के समाधान के लिए व्यवस्थित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं हैं। कंपनी क्रेडिट–जोखिम को कम करने के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली के साथ एक संरचित मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करती है। प्रचालन जोखिमों का प्रबंधन सभी कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक जोखिम रजिस्टर के माध्यम से किया जाता है। चलनिधि जोखिम को अग्रगामी संसाधन जुटाने सहित विभिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। एक व्यवस्थित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन ढांचे और सुपरिभाषित हेजिंग नीतियों के माध्यम से बाजार जोखिम का समाधान किया जाता है।

कंपनी की एक बोर्ड–स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति है जो इस क्षेत्र में विकास की निगरानी करती है और समय–समय पर अपनी सिफारिशें करती है। कंपनी में एक मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है, जैसा कि आरबीआई के मानदंडों के तहत अपेक्षित है। इसके अलावा, कंपनी ने आरबीआई की अपेक्षाओं के अनुरूप जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा संबंधी नीति और ढांचा अपनाया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी राष्ट्रीय सरोकार के विकास संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए, लाभार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम तक पहुंचने के लिए सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीएसआर पहलें करती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरईसी ने अपनी सीएसआर नीति के अनुसार विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं का समर्थन किया है, और कुल ₹171.07 करोड़ खर्च किए हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

मुझे यह उल्लेख करते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि समावेशी विकास की भावना को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने ओडिशा में गजपति, मिजोरम में मामित, नागालैंड में किफिर, बिहार में मुजफ्फरपुर, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, मणिपुर में चंदेल और सिक्किम में पश्चिम सिक्किम सहित विभिन्न आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण परियोजनाओं को प्रायोजित किया है।

समझौता-ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

समझौता–ज्ञापन (एमओयू) के संदर्भ में, आपकी कंपनी के प्रदर्शन को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा अधिकतम प्राप्तांक 100 के परफेक्ट स्कोर के साथ "उत्कृष्ट" दर्जा दिया गया है। आरईसी, पिछले वर्ष के समझौता–ज्ञापन मूल्यांकन में 100 में से 100 अंक हासिल करने वाला देश का एकमात्र सीपीएसई है।

इतना ही नहीं, आपकी कंपनी को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा अपने बीएफएसआई और फिनटेक अवार्ड्स में इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग श्रेणी में भारत की अग्रणी एनबीएफसी के रूप में नामित किया गया है; और एक्सचेंज4मीडिया द्वारा अपने महिला अचीवर्स अवार्ड्स में 'महिला सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन' के रूप में भी नामित किया गया है।

भावी पथ

'सभी के लिए 24x7 बिजली' जैसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ, हम निकट भविष्य में बिजली की विशाल मात्रा में मांग की उम्मीद करते हैं। बढ़ी हुई बिजली की मांग के लिए भी सुदृढ़ पारेषण और वितरण अवसंरचना की आवश्यकता होगी, जिससे इस क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित होगा। आरईसी, संपूर्ण मूल्य–श्रृंखला में विद्युत क्षेत्र की विविध जरूरतों के वित्तपोषण के लिए अनेक उत्पादों की पेशकश करता है।

नवंबर 2021 में यूके के ग्लासगो में सीओपी26 सत्र में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दुनिया के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक दूरदर्शी पंचामृत कार्यनीति का प्रस्ताव दिया है। इनमें वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% विद्युत मांग को पूरा करना, वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता में 45% की कमी और वर्ष 2070 तक कुल उत्सर्जन–निरपेक्षता प्राप्त करना शामिल है। हम ऊर्जा क्षेत्र और साथ ही मानव–जाति के लिए इन अत्यंत प्रासंगिक लक्ष्यों का समर्थन करते हैं।

इन लक्ष्यों के समर्थन के प्रयास में, आपकी कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, ई–मोबिलिटी अवसंरचना, सौर सेल और मॉड्यूल के निर्माण, हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा, पीएम–कुसुम परियोजनाओं, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, स्मार्ट–ग्रिड और स्मार्ट–मीटरिंग के लिए अपने वित्तपोषण में वृद्धि की है। आपकी कंपनी पीपीपी और फ्रैंचाइजी मॉडल के माध्यम से गैर–विद्युत अवसंरचना और वितरण कार्यों के वित्तपोषण के कार्य में कारोबार करने पर भी विचार कर रही है। आरईसी प्रतिस्पर्धी दरों पर संसाधन जुटाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ अनुरूपता लाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बहुपक्षीय विकास संगठनों के साथ घनिष्ठ साझेदारी का निर्माण कर रही है। मुझे आशा है कि आपकी कंपनी आने वाले समय में विद्युत एवं अन्य क्षेत्रों में सबसे अग्रणी बनने वाली है।

आभार

अपने शब्दों को विराम देने से पहले, मैं माननीय कैबिनेट मंत्री, विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, माननीय विद्युत राज्य मंत्री, सचिव (विद्युत) और विद्युत मंत्रालय के अन्य अधिकारियों को उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं, होल्डिंग कंपनी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों के अधिकारियों का उनके समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हूँ।

मैं, आरईसी के कॉरपोरेट सुशासन मानकों में लगातार सुधार करने के लिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, रजिस्ट्रार और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों को धन्यवाद देता हूँ।

आरईसी की सफलता मुख्य रूप से अपने हितधारकों के विश्वास और सद्भावना पर आधारित है और इसके लिए, मैं राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों और निजी क्षेत्र के उद्यमियों सहित सभी शेयरधारकों, डिबेंचर–धारकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं और ग्राहकों को धन्यवाद देता हूँ।

अंत में, मैं बोर्ड में अपने सम्मानित सहयोगियों को उनके कार्यनीतिक सुझावों और आरईसी के समस्त जनशक्ति को उनके अथक प्रयासों के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आरईसी को बड़ा और बेहतर बनाने के सफर की शुरूआत के लिए मैं आप सभी के बहुमूल्य योगदान की आशा करता हूँ।

धन्यवाद! जय हिंद!

शुभकामनाओं सहित,

विवेक कुमार देवांगन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

20 अगस्त, 2022